



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24092020-221950
CG-MH-E-24092020-221950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942

No. 375]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 10 सितम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/53/2014-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के गैर-पत्तन संबंधी कार्यकलापों के लिये पट्टे और लाईसेंस के प्रयोजन से सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र से इतर स्थान पर पत्तन भूमि और निर्मित स्थानों के आबंटन के लिये मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ सलग्न आदेशानुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या: टीएएमपी/53/2014-पीपीटी

परादीप पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर, 2020 के 8 वें दिन पारित)

यह मामला परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के गैर-पत्तन संबंधी कार्यकलापों के लिये पट्टे और लाईसेंस के प्रयोजन से सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र से इतर स्थान पर पत्तन भूमि और निर्मित स्थानों के आबंटन के लिये मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 पीपीटी संपदा के मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत, 11 जून 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/53/2014-पीपीटी के द्वारा अनुमोदित किये गये थे। उस आदेश के अनुसार पीपीटी संपदा के लिये अनुमोदित दर संरचना अनुसूची उक्त आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगी और पांच वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी। तदनुसार उक्त आदेश प्रशुल्क की वैधता 16 जुलाई 2020 तक निर्धारित करता है।

3.1. इस पृष्ठ भूमि में, पीपीटी ने 6 जुलाई, 2020 के अपने पत्र संख्या एडी/ईएसटी/विविध-III-06/2011(जिल्द-II) के द्वारा बताया है कि सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र से इतर पत्तन भूमि के बाज़ार मूल्य के आकलन के मार्च 2020 में नियुक्त मूल्यांकक कोविद – 19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लगाये गये लाकडाऊन के कारण मूल्यांकन नहीं कर पाया है। अतः पीपीटी अपनी संपदा के दरमान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त करता है।

3.2. इसी बीच, पीपीटी ने पीपीटी संपदा के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 11 जुलाई 2020 से और 6 महीने की अवधि के लिये करने का अनुरोध किया है।

4.1. पीपीटी ने अपने पत्र में संसूचित किया है कि पीपीटी संपदा की वैधता 10 जुलाई, 2020 को समाप्त हो रही है। यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि पीपीटी संपदा के दरमानों के आदेश की अधिसूचना भारत के राजपत्र में 17 जून, 2015 को हुई थी। संशोधित दरमान आदेश की अधिसूचना की तारीख 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होने थे। तदनुसार, पीपीटी संपदा के मौजूदा दरमानों की वैधता 16 जुलाई, 2020 को समाप्त हुई है न कि 10 जुलाई, 2020 को, जैसा कि पीपीटी ने संसूचित किया है।

4.2. चूंकि पीपीटी संपदा के मौजूदा दरमानों की वैधता 16 जुलाई, 2020 को पहले ही समाप्त हो गई है, और पीपीटी द्वारा ऊपर दिये गए कारणों से किये गये अनुरोध के आधार पर और प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिये, यह उपयुक्त समझा जाता है कि पीपीटी संपदा के मौजूदा दरमानों में 16 जुलाई, 2020 से और 6 महीने की अवधि के लिये या संशोधित दरमानों के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार किया जाये।

4.3. उक्त तथ्यों को देखते हुए, यह प्राधिकरण पत्तन भूमि और निर्मित स्थानों के आबंटन के लिये पीपीटी संपदा के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 17 जुलाई, 2020 से 16 जनवरी, 2021 तक अथवा पीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, करने को प्रवृत्त है, जैसा पीपीटी ने अनुरोध किया है।

4.4. इसके अतिरिक्त, पत्तन भूमि और निर्मित स्थानों के आबंटन के लिये, पीपीटी के मौजूदा दरमानों में, भू-नीति दिशानिर्देश 2014 में अंतर्विष्ट अनुबद्धता के आधार पर किरायों में @5% वार्षिक वृद्धि करना पहले से निर्धारित है। इसलिये, पीपीटी की भूमि और खाली स्थानों के आबंटन के लिये यथा लागू 5% की दर पर वार्षिक वृद्धि दरमानों की विस्तारित वैधता अवधि के दौरान भी लागू रहेगी।

5. परिणाम में और ऊपर दिये गये कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण पीपीटी के गैर-पत्तन संबंधी कार्यकलापों के लिये पट्टे और लाईसेंस के प्रयोजन से सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र से इतर स्थान पर पत्तन भूमि और निर्मित स्थानों के आबंटन के लिये मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार 17 जुलाई 2020 से 16 जनवरी, 2021 तक अथवा पीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है। 5% की दर पर वार्षिक वृद्धि दरमानों की विस्तारित वैधता अवधि के दौरान भी

लागू रहेगी। जहाँ तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का संबंध है, यह ध्यान में रखते हुए कि अब वैधता का विस्तार 16 जनवरी 2021 तक किया गया है, पीपीटी को सलाह दी जाती है कि संपदा प्रशुल्क के संशोधन का प्रस्ताव 31 अक्टूबर 2020 तक दायर कर दें।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-3/4/असा./233/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th September, 2020

No. TAMP/53/2014-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates (SOR) for allotment of Port land and built up space outside the Custom Bond area for leasing and licensing purpose for non-port related activities for Paradip Port Trust (PPT) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/53/2014- PPT

The Paradip Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 8th day of September, 2020)

This case relates to the extension of validity of the existing Scale of Rates (SOR) for allotment of Port land and built up space outside the Custom Bond area for leasing and licensing purpose for non-port related activities for Paradip Port Trust (PPT).

2.1 The existing Scale of Rates (SOR) of PPT Estate was approved by the Authority *vide* Order No. TAMP/53/2014-PPT dated 11 June 2015 under the Tariff Guidelines of 2005. As per the Order, the schedule of rate structure approved for PPT Estate had come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and was to remain in force for a period of five years. Accordingly, the Order prescribed a tariff validity till 16 July 2020.

3.1. In this backdrop, the PPT *vide* its letter dated no. AD/EST/MISC-III-06/2011 (Vol-II) dated 06 July 2020 has stated that, the valuer appointed to assess the market value of the port land outside Customs Bonded area in March 2020 has not been able to make any progress in valuation, due to lockdown imposed by Government due to COVID-19 pandemic. As such the PPT has expressed its inability to submit a proposal for revision of SOR of PPT Estate.

3.2. In the meanwhile, the PPT has requested to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT Estate for a further period of 6 months w.e.f. 11 July 2020.

4.1. The PPT in its letter has conveyed that the validity of PPT Estate expired on 10 July 2020. However, it is relevant to mention here that the Order notifying SOR for PPT Estate was notified in the

Gazette of India on 17 June 2015. The revised SOR was to come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of Order. Accordingly, the validity of SOR of PPT Estate has expired on 16 July 2020 and not 10 July 2020, as conveyed by PPT.

4.2. Since the validity of the existing tariff of PPT Estate has already expired on 16 July 2020 and based on the request made by PPT for the reasons cited by it and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of PPT Estate for a further period of 6 months beyond 16 July 2020 or till effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

4.3. In view of the above, this Authority is inclined to extend the validity of the existing SOR of PPT for allotment of port lands and built space for a period of 6 months with effect from 17 July 2020 to 16 January 2021 or till the effective date of implementation of the revised SOR, based on the proposal to be filed by PPT, whichever is earlier, as requested by PPT.

4.4. Further, the existing SOR of PPT for allotment of port lands and built space already prescribe an annual escalation @ 5% in the rentals, based on the stipulation contained in the Land Policy Guidelines, 2014. Therefore, the said annual escalation @ 5% shall continue to apply during the extended validity period of the SOR as applicable for allotment of port lands and built space of PPT.

5. In the result and for the reasons given above and based on the collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing SOR of PPT for allotment of port lands and built up space outside the custom Bond area for leasing and licensing purpose for non-port related activities of PPT from 17 July 2020 till 16 January 2021 or till the effective date of implementation of the revised SOR based on the proposal to be filed by PPT, whichever is earlier. The annual escalation of 5% in the rental shall continue to apply during the extended validity period. With regard to submission of the proposal, considering that the validity extended upto 16 January 2021, the PPT is advised to file its proposal for revision of its Estate tariff by 31 October 2020.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-3/4/Exty./233/2020-21]